<u>तुरंत जारी किए जाने के लिए</u>

विश्व बैंक

समाचार रिलीज़ सं. 2005/513/एसएआर

संपर्क-सूत्र: *दिल्ली में:* सुदीप मजूमदार (91 11) 2461-7241
ई-मेल: smozumder@worldbank.org
वाशिंगटन में: बेंजामिन क्रो (202) 473-5105
ई-मेल: bcrow@worldbank.org

विश्व बैंक द्‌वारा भारत के शहरी विकास में मदद

तमिल नाडु शहरी विकास परियोजना के लिए 30 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता

वाशिंगटन, 5 जुलाई, 2005: विश्व बैंक ने तीसरी तमिल नाडु शहरी विकास परियोजना *(थर्ड तमिल नाडु अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट- टीएनयूडीपी-III)* के क्रियान्वयन में भारत सरकार की मदद करने के लिए आज यहां 30 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना का उद्‌देश्य शहरी संरचना *(इन्फ्रास्ट्रक्चर)* की क्वालिटी बढ़ाते हुए, शहरी संरचना में निवेश के लिए सतत आधार पर संसाधन जुटाते हुए तथा शहरी स्थानीय निकायों की संस्थागत और वित्तीय संरचना को सुदृढ़ करते हुए शहरी सेवाओं की डिलीवरी में सुधारों को जारी रखना है।

लगभग 30 करोड़ शहरी निवासियों के साथ भारत के नगर सकल घरेलू उत्पादन में 60 प्रतिशत से अधिक का अंशदान करते हैं और सरकारी राजस्व का 90 प्रतिशत से अधिक इन्हीं नगरों से मिलता है। लेकिन, अगर ये नगर संरचना-संबंधी भारी बाधाओं, सेवाओं की अकुशलताओं, ज़मीन के और फ़ैक्टर बाज़ार की विकृतियों, कमज़ोर वित्त और ढीले स्थानीय प्रशासन का शिकार न रहे होते, तो इनका यह अंशदान कहीं अधिक कारगर रहा होता। तमिल नाडु की लगभग 47 प्रतिशत जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है, जो भारत का एक सर्वाधिक ऊंचा प्रतिशत है।

विश्व बैंक के कंट्री डाइरेक्टर माइकेल कार्टर ने कहा: *"हालांकि शहरी कार्यकुशलता का देश की सकल अर्थव्यवस्था पर उल्लेखनीय और सीधा प्रभाव पड़ता है, इसके बावजूद चंद एक नगर ही ऐसे हैं, जो नियमित और सतत आधार पर शहरी सेवाएं सुलभ कराने में समर्थ हैं। यह परियोजना* टीएनडीयूपी-II *की उपलब्धियों - व्यापक-स्तरीय शहरी सुधार और स्थानीय शहरी निकायों की क्षमता का सुदृढ़ीकरण - के बल पर और इन्हें समेकित करते हुए तमिल नाडु में शहरी संरचना (बुनियादी सेवाओं) में सतत रूप से सुधार जारी रखेगी।"*

यह परियोजना शहरों में बुनियादी सुविधाओं के लिए धन मुहैया कराएगी, जैसे जल आपूर्ति और सफ़ाई, भूमिगत *सीवरेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट* प्रबंध, *स्ट्रीट लाइट,* शहरी सड़कें और यातायात-प्रबंध से जुड़ी गतिविधियां। इस परियोजना में सड़कों को चौड़ा और प्रबलित करते हुए तथा सड़कों पर *अंडर* और *ओवर* ब्रिज का निर्माण करते हुए चेन्नै महानगरीय क्षेत्र में सड़कों तक पहुंच में सुधार करना भी शामिल है। इसके अलावा, इस परियोजना में परिवहन अवरुद्‌धता *(ट्रांसपोर्ट कंजेशन)* की समस्या हल करने के लिए यातायात प्रबंध के मुद्‌दे पर भी ध्यान दिया जाएगा।

इस परियोजना के तीन मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

- राज्य-स्तर के निकायों से शक्तियों के प्रत्यायन *(डेलिगेशन ऑफ पॉवर्स)* के जरिए विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को जारी रखते हुए **शहरी स्थानीय निकायों की अधिकारिता को सुदृढ़ करना**; और क्षमता का निर्माण करने से संबधित कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखना।

- तमिल नाडु शहरी विकास कोष की मध्यस्थता के जरिए स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय बाज़ारों से जोड़कर निजी वित्त के जरिए **शहरी संरचना में निवेश के लिए सतत आधार पर संसाधन जुटाना**; और समर्थनकारी पूंजीगत अनुदानों के जरिए निम्न आय वाले पड़ोस में निवेश के लिए *इंसेन्टिव्स* मुहैया कराना।

- दूसरी नगरपालिकाओं के लिए सफल मॉडल सुलभ कराना। इन दिनों, शहरी नगरपालिकाओं को कुछ ही जगहों से ऋण मिल सकता है, जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी से गठित *फाइनैंशियल इंटरमीडियरी* संस्था - तमिल नाडु शहरी विकास कोष।

भारत सरकार की दसवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2002-2007) में अर्थव्यवस्था में संवृद्धि *(ग्रोथ) के लिए* और निर्धनता कम करने की दृष्टि से शहरी सुधारों को महत्त्वपूर्ण बतलाते हुए इन पर ज़ोर दिया गया है। यद्यपि, अनुमान है कि इस अवधि में शहरी विकास के लिए लगभग 7 अरब डालर की ज़रूरत होगी, लेकिन यह लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए राज्य और स्थानीय दोनों ही स्तरों पर सुधारों के महत्त्व को स्वीकार किया गया है।

विश्व बैंक में *इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस* की एक वरिष्ठ विशेषज्ञा आभा जोशी-ग़नी ने कहा है: *''विश्व बैंक भारत की शहरी सुधार कार्यसूची का निरंतर समर्थन कर रहा है, जिसमें एक व्यापक विकेन्द्रीकरण संरचना , नागरिकों की अधिकारिता के सुदृढ़ीकरण, शहरी प्रबंध, शासकीय कामकाज* (गवर्नेंस) *और संसाधन जुटाने पर ज़ोर दिया गया है। इस परियोजना से सुधार-प्रक्रिया में और गतिशीलता आएगी, स्थानीय स्तर पर वित्त सुलभ होगा, स्थानीय शहरी निकाय पूंजी बाज़ारों तक पहुंच बनाने में सफल होंगे और इस तरह निवेश-संबंधी आवश्यकताओं के लिए केन्द्र व राज्य के सीमित बजटीय संसाधनों पर इनकी निर्भरता कम होगी।''*

विश्व बैंक की ऋण मुहैया कराने वाली संस्था *इंटरनेशनल बैंक फ़ॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी)* से मिलने वाला यह ऋण 20 वर्ष में देय है। इसका भुगतान पांच वर्ष बाद शुरू होगा।

#####

भारत में विश्व बैंक की गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए
कृपया वेबसाइट *www.worldbank.org/in* देखें।